

**कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील
हुजूर जिला भोपाल**

प्रारूप - पाँच

(देखिय नियम 12)
कालोनी के विकास की अनुमति

तारीख 25 / 11 / 2010

अनुमति क्रमांक 17 / 2010
प्र0क07 / बी-121 / 2010-11

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1999) और उसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए:-

आवेदक आर.आर.जी.बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री मनोहर पाटीदार आ0 श्री राजाराम गुजराती पता - जेड-22 मनोरम काम्पलेक्स जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल को ग्राम पंचायत छान के ग्राम छान स्थित भूमि खसरा क्रमांक 296/1, 297, 298, 299, रकबा क्रमशः 1.51, 1.40, 0.64, 0.70 हेक्टेयर कुल रकबा 4.250 हेक्टेयर पर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अन्तर्गत आवासीय विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदाय की जाती है:-

1. (शहरी भूमि सीमा अधिनियम) 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भूखंडों/भवनों का विकास /निर्माण प्रथमतः करना अनिवार्य होगा।
5. सम्पूर्ण विकास कार्य प्रमाण पत्र जारी होने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।
6. निम्नलिखित अधिनियम /नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/ अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता 1959

राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)



25/11/2010
अनुविभागीय अधिकारी
हुजूर भोपाल

- 6.3 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
- 6.4 जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
- 6.5 भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल
7. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अन्तर्गत कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के आधार पर पूर्ण करना होगा विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से भी अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा।
8. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हावैस्टिंग /रूफ वाट हावैस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी।
9. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी /संस्था की होगी।
10. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित एवं अनुमोदित मार्गों को निरंतरता सुनिश्चित रखी जाय एवं आसपास के भू-स्वामियों से मार्गों की निरंतरता हेतु सहमति प्राप्त करना होगा एवं अपूर्ण भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर
12. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनिवार्यतः की जावे।
13. भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन करवाने के पश्चात् अनुमोदित अभिन्यास को स्थल पर चिह्नित करवाकर अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन करवाना आवश्यक होगा, अन्यथा चिन्हांकन के बगैर किया गया विकास कार्य अवैध मान्य किया जावेगा।
14. अनुमोदित अभिन्यास की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
15. मार्गों का पूर्ण विकास, विद्युत प्रदाय (स्ट्रीट लाईट) जल प्रदाय आवेर हेड टैंक सेप्टिक टैंक, पार्कों का विकास, खुले क्षेत्रों तथा मार्गों के किनारे वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक सेवा सुवधाओं। अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
16. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
17. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 ग 1.25 मीटर साईज बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा व इसे विकास स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावे जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सके।



25/11/2010
 अनुविभागीय अधिकारी
 वृह. हजूर भोपाल

(3)

18. संस्था एवं संबंधित विभाग को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
19. एच.टी.लाईन एवं इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भू-खण्ड अन्य मान्य नहीं होंगे इन पर भवन अनुज्ञा न दी जावे।
20. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है, साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
21. अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे।
22. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है। उनमें सीवेज टैंक, ओवर हेड टैंक, गारवेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादित किया जावे।
23. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों का सम्पूर्ण करने के पश्चात् ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
24. भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य प्रकार किया जावे कि भवन का आसपास के समुचित कलर स्कीम प्रयुक्त की जानी होगी।
25. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी।
26. उक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विकास अनुमति निरस्त की जावेगी।
27. कालोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी अनुमोदित अभिन्यास में लाल रंग से दर्शाये अनुसार खसरा क्रमांक 296/1, 297, 298, 299, रकबा क्रमशः 1.51, 1.40, 0.64, 0.70 हेक्टेयर कुल रकबा 4.250 हेक्टेयर में से पच्चीस प्रतिशत के मान से बंधक क्षेत्रफल 45249.25 वर्गमीटर में स्थित निर्मित प्रथम तल के फ्लेट क्रमांक सी-101 से सी-126 कुल 26, द्वितीय तल के फ्लेट क्रमांक सी-201 से सी-230 कुल 30, तृतीय तल के फ्लेट क्रमांक सी-301 से सी 330 कुल 30, चतुर्थ तल के सी-401 से सी-430 कुल 30, पांचवा तल के सी-501 से सी-530 कुल 30 फ्लेट इस प्रकार कुल 146 फ्लेट जिसका कुल बंधक क्षेत्रफल 11315 वर्गमीटर जो बंधक पत्र के साथ संलग्न अनुमोदित अभिन्यास में लाल रंग से रेखांकित किये गये हैं जो रजिस्टर्ड बंधक पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 को ग्राम पंचायत छान में बंधक रखा है जो कालोनी का आंतरिक विकास पूर्ण करने पर इस कार्यालय द्वारा बंधक मुक्त किया जावेगा।

इस प्रकार अनुमति को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।

यदि प्रदाता की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
यदि प्रदाता से आदेश जारी नहीं किये जावेगें।



Photo Copy Attested

H. N. MALVIYA
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL, M.P., INDIA

सक्षम पाण्डित्य एवं अनुमोदित अधिकारी
(राजस्थान) तहसील इंदौर जिला भोपाल
27/11/2010